less orders given to the factory. Although, the factory has enough buildings, land, technical knowhow, etc. to accommodate and to employ double the number of workers, if the workload is increased. I would ask the Minister to secure large number of orders such as stitching of uniforms for para-military Forces, i.e., Border Security Force, Central Reserve Police, Indo-Tibetan Border Police, Industrial Security Force, Railway Protection Force and Civil and Armed Police of Area State. There are many items of clothing uniforms which are required by the Armed Forces but are being manufactured by private companies. All these items should be diverted to the Ordnance Clothing Factory, Shahjahanpur so that the employment potential of this factory is increased by hundred per cent which in turn will reduce unemployment and also supply better quality goods to the Armed Forces and other Government organisations.

(iii) STEPS TO ABOLISH DEVDASI SYSTEM IN KARNATAKA.

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी ही पीड़ा एवं लज्जा का विषय है कि 33 साल की आजादी के बाद भी आज देश के एक भाग—कर्नाटक—में देवदासी प्रथा प्रचलित है। दकियानूसी विचारों एवं अंध विश्वासों पर आधारित, भोग विलास में लिप्त स्वेण पुजरियों द्वारा धर्म की आड़ में अनभिज्ञ एवं निरीह अबलाओं के साथ सदियों पुराना चला आ रहा यह कुचक्र आज स्वतन्त्र भारत के मस्तिष्क पर कलंक का टीका मात्र बन कर रह गया है। विदित हुआ है कि आज भी प्रतिवर्ष लगभग पांच हजार देवदासियां बनाई जा रही हैं। उनमें अधिकांश बम्बई, पुणे, कोल्हापुर आदि नगरों में अपनी अस्मत बेचने को बाध्य हो रही हैं। यह नारी उत्पीड़न की पराकाष्ठा है। यह कितना अमानवीय है कि 5, 6 वर्ष की अबोध बालिकाएं देवदासी बना दी जाती हैं और वे जीवन पर्यन्त कठोर यातनाएं सहती रहती हैं।

क्षोभ की बात है कि इस घृणित प्रथा के उन्मूलन के लिए जो भी उपाय अपनाये गए वे पूर्णरूपेण प्रभावहीन हैं। 1907 में मैसूर के तत्कालीन महाराजा ने इस प्रथा पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। तत्पश्चात् ब्रिटिश शासन में 1934 में देवदासी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। परन्तु निष्ठा के अभाव में इनका कार्यान्वियन विशेष लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ।

मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से सविनय आग्रह करूंगा कि जो भी उपाय आवश्यक हों, तत्काल कठोरता से अपनाये जाएं जिससे इस लज्जाजनक प्रथा का अविलम्ब उन्मूलन हो सके। साथ ही वर्तमान देवदासियों के पुनर्वास एवं जीविकोपार्जन के लिए प्रभावकारी एवं व्यावहारिक कार्यक्रम चलाये जायें जिससे उन्हें अपनी दुखियारी जिन्दगी में कुछ राहत मिल सके।

(iv) REPORTED CLOSURE OF THE JAWAHAR LAL NEHRU UNIVERSITY'S CENTRE OF STUDIES IN SCIENCE POLICY.

SHRI K. A RAJAN (Trichur): Sir, it is reliably learnt that the J. N. U. authorities are toying with the idea of closing down the University's centre of studies in Science policy. This will jeopardise the careers of students.

The Ramanna Committee was appointed to formulate a workable programme for study of science policy in the University, not to kill what is existing.

Even prior to the Ramanna Committee Report, the Centre had virtually been suspnded since last March.

[Shri K. A. Rajan]

This closure step would virtually mean, throwing out students on the verge of completion of their research.

No university order was passed and yet the authorities arbitrarily changed the basic structure of the Centre.

Therefore, I urge upon the Government to put a stop to this ill-advised move to close the said Centre.

(v) NEED FOR SETTING-UP A BENCH OF ALLAHABAD HIGH COURT AT BAREILLY.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के बरेली नगर में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बैंच खोले जाने के लिए बरेली व उसके आसपास के 8, 10 जिलों के वकील कई दिन से हड़ताल कर के व अदालतों का बहिष्कार कर के सार्वजनिक सभायें व जुलूसों का आयोजन कर रहे हैं। सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में पिथौरागढ़, चमोली, टेहरी, अल्मोड़ा नैनीताल के निवासियों को भी बरेली में हाई कोर्ट की बैंच स्थापित होने से अत्याधिक लाभ होगा। वकीलों व जनता की यह मांग सर्वथा उचित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अठारह हजार मुकदमे अनिर्णीत पड़े रहना भी इस मांग का औचित्य सिद्ध करता है। अतः सार्वजनिक महत्व के इस प्रश्न पर मैं माननीय विधि एवं न्याय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए बरेली में हाई कोर्ट की बैंच की स्थापना की मांग करता हूं।

(vi) REPORTED DISAPPEARANCE OF A DISTRICT AND SESSIONS JUDGE OF RAJASTHAN SINCE 16TH MARCH, 1981.

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL (Kota): A District and Session Judge of Rajasthan disappeared mysteriously since March 16, 1981. Shri Mangat Ram Mitruka of Jhunjhuni, who is under transfer orders, left the residence of Shri R. L. Gupta in pursuit of some persons moving outside the house in suspicious circumstances. Shri Mitruka had come to Delhi with documentary evidence to expose the corruption pre-vailing in Rajasthan judiciary. Shri Mitruka had met Chief Justice of India, on March 9 about the documents in his possession. Some suspicious persons were following Shri Mitruka around in Delhi and visited his room in Birla Mandir where he was staying. Later on he shifted to the residence of Shri R. L. Gupta, Additional District Judge, Delhi. But even at the residence of Shri Gupta, some persons were after him. On March 16, Shri Mitruka went after the persons standing outside the house of Shri Gupta in suspicious circumstances. Shri Mitruka had collected documentary evidence on corruption in the Rajasthan judiciary in his capacity as Vigilance Register of the Rajasthan High Court. In the past Shri Mitruka had received several threats to his life. His sudden mysterious disappearance has caused serious concern I request the Union Law and Home Ministers to help in tracing Shri Mitruka.

(vii) STEPS TO IMPROVE DISTANT COMMUNICATION FACILITIES IN BACKWARD DISTRICTS OF UTTAR PRADESH.

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जनपद दूरसंचार सेवाओं के संदर्भ में बहुत पिछड़े हुए हैं, जिसके कारण-स्वरूप यहां के लोगों को बहुत अधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है :—

(1) यहां के जनपदों के मुख्यालयों को माइक्रोवेव प्रणाली द्वारा लखनऊ व देहली से जोड़ा जाना आवश्यक है, ताकि प्रदेश की व देश की राजधानी से यहां के लोगों का सीधा सम्बन्ध जुड़ सके।